



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94/2018

1 धोलूराम पुत्र पोखर उम्र 60 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांत

बनाम

- 1 भूराराम पुत्र छीतरमल।
- 2 नन्दलाल पुत्र भूराराम।
- 3 प्रभात पुत्र भूराराम।
- 4 संतोष पुत्री भूराराम।
- 5 ज्ञानी पुत्री भूराराम।
- 6 जीवा पुत्री भूराराम।
- 7 मुन्नी पुत्री भूराराम।
- 8 पाँची पुत्री भूराराम समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 9 ओमप्रकाश पुत्र भोलूराम।
- 10 गोकुल पुत्र धूड़ाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण नाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 11 कमला पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 12 सुखदेवी पत्नी लादुराम जाति कुमावत निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 13 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 14 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 15 मंगलाराम पुत्र पोखर।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी  
सीकर



16 रामेश्वर पुत्र पोखर।

17 मोहन पुत्र पोखर।

18 रामस्वरूप पुत्र पोखर समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्ली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 27/2007 बउनवानी भूराराम बनाम मंगलाराम आदि दिनांक 26.02.2008


अपील संख्या 95/2018

1 धोलूराम पुत्र पोखर उम्र 60 वर्ष जाति रैगर निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

- 1 भूराराम पुत्र छीतरमल।
- 2 नन्दलाल पुत्र भूराराम।
- 3 प्रभात पुत्र भूराराम।
- 4 संतोष पुत्री भूराराम।
- 5 ज्ञानी पुत्री भूराराम।
- 6 जीवा पुत्री भूराराम।
- 7 मुन्नी पुत्री भूराराम।

  
कृपलका अधिकारी एवं  
पदेन तत्काल अपील अधिकारी  
सीकर




- 8 पांची पुत्री भूराराम समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 9 ओमप्रकाश पुत्र भोलूराम।
- 10 गोकुल पुत्र धूडाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण नाड़ा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 11 कमला पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 12 सुखदेवी पत्नी लादुराम जाति कुमावत निवासी ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 13 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 14 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
- 15 मंगलाराम पुत्र पोखर।
- 16 रामेश्वर पुत्र पोखर।
- 17 मोहन पुत्र पोखर।
- 18 रामस्वरूप पुत्र पोखर समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 24.02.2009 एवं तदन्तर्गत संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर दावा संख्या 27/2007 बउनवानी भूराराम बनाम मंगलाराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

  
प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राज्य अपील अधिकारी  
सीकर



—निर्णय—

दिनांक:- 18-2-20

यह दोनों अपीलें विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 27/2007 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2009 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 12.12.2012, दिनांक 26.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग-अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में भूमियां खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1552/1120 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1551/1120 रकबा 6.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1582 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120/1553 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.86 हैक्टेर अवस्थित है। भूमियां खसरा नम्बर 1552/1120 रकबा 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1551/1120 रकबा 6.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 6.83 हैक्टेयर का ही भाग रही है। भूमि खसरा नम्बर 1151/1120 संपरिवर्तन के पश्चात खसरा नम्बर 1120 में से ही एक खसरा नम्बर के रूप में रही है। उपरोक्त भूमियों के 3/4 हक, हिस्से के रिकार्डेंड काबिज, खातेदार काश्तकार अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 15 लगायत 18 है। शेष 1/4 हक, हिस्सा रेस्पोंडेंट संख्या 1 का है, जिसमें से उसके द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 10 तथा रेस्पोंडेंट संख्या 12 के हक में अवैध हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करवाये गये है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 10 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 11 के हक में अवैध हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 14.02.2007 को विवादित भूमियों के बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के निमित्त अपीलाधीन वाद योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें बिना अपीलांट की विधिवत तामील करवाये

पक  
भूमि एवं पक्षकार अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर



बिना तथा तामिली आदेश के बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 26.02.2008 अपीलाधीन वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई तथा दिनांक 24.02.2009 को बिना अपीलांट को किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई। इसके पश्चात दिनांक 12.12.2012 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध रूप से निर्णय व संशोधित अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई इससे व्यथित होकर यह प्रथक प्रथक अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में अपीलांट के नोटिस की विधिवत तामिल नहीं हुई, तामिल का कोई आदेश नहीं हुआ, बिना तामिल के विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 26.02.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसमें भी दिये गये आदेश की पालना नहीं की गई है। दिनांक 24.02.2009 को अन्तिम डिक्री जारी हुई, इजराय का आवेदन पेश हुआ, पटवारी की रिपोर्ट में वादी द्वारा दौराने वाद कई भूमियों का बेचान होने की रिपोर्ट आई, इन क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इनको पक्षकार बनाये बिना संशोधित विभाजन प्रस्ताव का आदेश एवं संशोधित अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव हिस्से अनुसार नहीं है। अपीलांट को सम्यक तामिल करवाये बिना विचाराधीन आदेश पारित करवाये गये है। अपीलांट को इनकी जानकारी नहीं थी। जानकारी से अन्दर मियाद अपीले प्रस्तुत कर दी है। प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अपीले स्वीकार कि जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में भूराराम का 1/4 हिस्सा है। भूमियों का रूपान्तरण हो चुका है, आवासीय हो चुकी है, बंटवारा होने के बाद विभिन्न लोगो को बेची जा चुकी है, क्रेताओं को पट्टे मिल चुके है एवं विवादित भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है।

  
प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राज्य अपील अधिकारी  
कर



विचाराधीन निर्णय की पूर्व में अपील संख्या 19/2016 प्रभात बनाम भूरा भूरा के लड़के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो खारिज हो चुकी है। अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में सम्यक तामिल नहीं हुई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि तामील के विरुद्ध पक्षकार द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के तहत चाराजोही करनी चाहिए ऐसा नहीं करने पर वह पक्षकार अपील के स्तर पर तामील की आपत्ति नहीं उठा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई चाराजोही नहीं की है। अब इस बिन्दु पर अपील के स्तर पर कोई लाभ लेने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन किया है। किसी भी पक्षकार का रकबा कम नहीं किया है विवादित भूमि के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें मौका कमिश्नर द्वारा दिनांक 05.01.2017 को मौका देखा गया था। उसमें अपीलांट स्वयं उपस्थित था। ऐसी स्थिति में जानकारी नहीं होने का कथन मिथ्या है अपीलांट धारा 5 का लाभ नहीं ले सकता है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय में अपीलांट के नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई, तामील का कोई आदेश नहीं हुआ, बिना तामील के विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। दिनांक 26.02.2008 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसमें भी दिये गये आदेश की पालना नहीं की गई है। दिनांक 24.02.2009 को अन्तिम डिक्री जारी हुई, इजराय का आवेदन पेश हुआ, पटवारी की रिपोर्ट में वादी द्वारा दौराने वाद कई भूमियों का बेचान होने की रिपोर्ट आई, इन क्रेताओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इनको पक्षकार बनाये बिना संशोधित विभाजन प्रस्ताव का आदेश एवं संशोधित अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं

पञ्जाब प्रभु-पक्ष अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
कर

